संविधान में भी राम का जिक्र है, जो राम को नहीं मानते वे संविधान का अपमान कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा

राजस्थान इंटरनैशनल सैंटर में आयोजित इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के राष्ट्रीय सेमीनार में मु.मंत्री भजन लाल ने कहा, इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा प्रभावी साबित हो रही है

- **विश्व इलैक्ट्रोपैथी दिवस पर आयोजित सैमीनार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संविधान में राम-सीता, लक्ष्मण के फोटो छपे हुए हैं।**
- **मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि, इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, यहां 2018 में इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा विधेयक पारित हुआ था। राज्य सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।**

जयपुर, 13 जनवरी (का.सं.)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर "रीनल डिस्ऑर्डर्स एंड इलेक्ट्रोपैथी एप्रोच" विषयक सेमिनार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुनिया को यह पद्धति देने वाले काउंट सीजर मैटी को नमन किया। मुख्य अतिथि के रुप में सैमिनार में शामिल हुए इस दौरान उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। जो लोग राम को नहीं मानते हैं, वे संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। राष्ट्र हित को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि, संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। संविधान में भी देखें तो राम-सीता और लक्ष्मण के फोटो छुपे हुए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया है। धनखड़ के बयान को कांग्रेस के फैसले से जोड़कर ही देखा जा रहा है।

धनखड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि, यह आपको सौभाग्य मिला है और मुझे भी मिला है कि, मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली है। अब आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी होगी। समाज भी तभी काम करेगा, जब शरीर की तरह सभी अंग काम करेंगे। जब भारत आजादी के स्वर्णिम 100 साल मनाएगा, तब भारत दुनिया में सिरमौर होगा।

कार्यक्रम के दौरान धनखड़ ने पिछली गहलोत सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय जब मैं राजस्थान आया तो मेरा हेलिकॉप्टर उतरने नहीं दिया। तब प्रेमचंद बैरवा के सहयोग से स्थानीय किसान ने जिला कलेक्टर को लिखकर दिया कि मेरे खेत में 3 नहीं 13 हेलिकॉप्टर उतरवाएं।

सैमिनार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि जनसेवा का श्रेष्ठ मार्ग चिकित्सा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा में औषधीय पौधों के रसों के जरिए उपचार किया जाता है। यह प्रभावी चिकित्सा पद्धित के रूप में उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियां विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी साबित हुई हैं। शर्मा ने कहा कि काउंट सीजर मैटी मानते थे कि, हमारा भोजन पेड़-पौधे ही हैं तो उपचार भी औषधीय पेड़-पौधों के जरिए खोजना चाहिए। राजस्थान में भी रोगियों का उपचार इस पद्धित से हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धित को मान्यता देने वाला देश में प्रथम राज्य है। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धित विधेयक, 2018 पारित किया। इस पद्धित को आगे बढ़ाने और रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

सेमिनार में उपमुख्यमंत्री व आयुर्वेद मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस पद्धित को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आवश्यक निर्णय लेगी। इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की पुस्तिका का विमोचन और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, चूरू सांसद राहुल कस्वां, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, परिषद के पदाधिकारी और इलेक्ट्रोपैथी पद्धित चिकित्सक सहित विशेषज्ञ उपस्थित थे।

राजस्थान इंटरनैशनल सैंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार को उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा मुख्यमंत्री भजनलाल ने संबोधित किया।

'अपने स्वार्थ के लिए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस खेल में, कांग्रेस उनके लिए सहायक हो सकती है और तृणमूल कांग्रेस के लिए ऐसी मान्यता हासिल करने के लिए बंगाल में कांग्रेस को कुछ रियायत देना उनके लिए सार्थक होगा। तथापि, इस तरह के किसी समझौते के लिए राजी होना कांग्रेस के लिए बेवकूफी होगी।

ममता का पूरा राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी की पीठ तोड़ने के लिए रहा है और मिज़ोरम, गोवा व त्रिपुरा के पिछले चुनावों में ममता ने इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपनी उपस्थिति को बेहतर करने की कोशिश की थी।

जमीनी स्तर पर, स्थानीय कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भावनाएं इतनी अधिक ममता विरोधी हैं कि, उच्च स्तर पर यदि दोनों पार्टियों में किसी तरह का समझौता हुआ तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता एवं नेता पूरी तरह से इसे नाकाम करेंगे। राज्य स्तर के सभी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौते का विरोध किया है।

लेकिन, ममता बनर्जी के लिए वामपंथियों का ऐसा कोई महत्व नहीं है। वामपंथी राज्य में स्वयं विलुप्ति के कगार पर हैं और केरल में भी उनके पास सीमित सीटें हैं। इसलिए ममता सीट शेयरिंग में वामपंथियों के साथ किसी तरह के रियायत की उम्मीद नहीं कर सकतीं। इसीलिए उन्होंने माकपा के साथ किसी भी तरह के चुनावी समझौते से स्पष्ट इंकार कर दिया है।

इस रणनीति के विरोधाभास बिल्कुल स्पष्ट हैं। कांग्रेस और माकपा पूर्व में कुछ सीट शेयरिंग समझौता कर चुके हैं, हालांकि, सीटें हासिल करने की दृष्टि से इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। एक के साथ समझौता और दूसरे को अस्वीकार करना अजीब लगता है तथा दोनों खिलाड़ियों, कांग्रेस व माकपा के लिए यह संबंधों का अंत नज़र आता है।

माकपा का इतना जबरदस्त विरोध अस्तित्व की लड़ाई भी है। ममता के विरूद्ध कुछ ताकतों को इकट्ठ करने में माकपा सफल रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। इससे अल्पसंख्यक वोटों पर ममता की अभी तक की पकड़ कम हुई है। वो दोनों तरफ से घिर गई हैं, बहुसंख्यक वोट उनसे दूर जा रहे हैं और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर माकपा सेंध लगा रही है।

लेकिन, तृणमूल कांग्रेस एवं इण्डिया गठबंधन, मुख्यतः कांग्रेस व माकपा, के बीच सीट शेयरिंग की सारी बातें खोखली हैं। सभी विपक्षी दलों के प्रति तृणमूल कांग्रेस की, प्रतिशोध की क्रूर राजनीति के कारण तृणमूल पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता।

कर्नाटक और तेलंगाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद अब कांग्रेस को उम्मीद है कि वह यहां की कुल 28 लोकसभा सीटों में से दस या उससे अधिक सीटें जीत सकती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां सिर्फ दो सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी।

स्थानीय कन्नड़ मीडिया की कुछ खबरों के अनुसार कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व ने प्रियंका को चुनावी समर में उतारने के लिए कोप्पल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को चिन्हित किया है। कोप्पल कर्नाटक के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। इस निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस के लिए सर्वाधिक सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि इस जिले के कुल आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से छः पर कांग्रेस का कब्जा है।

वर्तमान में भाजपा के कराडी संगना कोप्पल से लोकसभा सांसद हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि कोप्पल से प्रियंका को उम्मीदवार बनाने का समूचे कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा और वे नए उत्साह के साथ और कड़ी मेहनत करेंगे।

पुराने कांग्रेसी बताते हैं कि प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी ने भी वर्ष 1977 की पराजय के बाद संसद में वापसी के लिए वर्ष 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चयन किया था। अब इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर उडूपी-चिकमंगलुरु हो गया है। वर्तमान में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शोभा करांदलजे यहां से सांसद हैं।

प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी तक ने वर्ष 1999 में बेल्लारी से चुनाव लड़ा था जहां उनका मुकाबला सुषमा स्वराज से था। इस बहुचर्चित चुनाव में सोनिया बहुत ही कम मतों के अन्तर से विजयी रही थीं।

तेलंगाना के कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी मेंडक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी यहां से वर्ष 1980 में चुनाव जीती थीं। स्थानीय नेताओं का तर्क है कि वोटर्स के लिए प्रियंका गांधी की अपील और करिश्मा ठीक वैसा ही है, जैसा उनकी दादी का हुआ करता था, खासतौर पर आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही भाग था, वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री अनामुला रेवंत रेड्डी का मानना है कि यदि मेडक नहीं तो, फिर प्रियंका राज्य की किसी भी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का विचार कर सकती हैं। वह कहीं से भी चुनाव जीत सकती हैं।

रामनवमी को अयोध्या ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल व प्रियंका राम नवमी के दिन आगामी 17 अप्रेल को भगवान के दर्शनार्थ अयोध्या जाएं, उस समय लोकसभा चुनाव नजदीक होंगे। वे भगवान राम के प्रति अनादर का भाव दिखाना नहीं चाहते, ऐसा करके उन्होंने भाजपा व आर.एस.एस. द्वारा मंदिर उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी तय करने की हवा निकाल दी है।

चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि, यह कवायद भाजपा के 22 जनवरी को मंदिर उद्घाटन के पीछे छिपा उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अभी मंदिर का निर्माण कार्य भी सम्पूर्ण नहीं हुआ है और इसी कारण से देश के सभी सम्मानित शंकराचार्यों भाजपा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उनका आरोप है कि भाजपा हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण कर प्राप्त करने के लिए राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है।

विश्लेषकों का कहना यह भी है कि कांग्रेस द्वारा राम नवमी की रणनीति अपनाने से कांग्रेस को किसी भी प्रकार के नुकसान के बजाए फायदा ही होगा। जबकि कुछ आलोचक नुकसान का पहले दावा कर रहे थे।

अगले एक सप्ताह तक जनता के अयोध्या आने-जाने पर रोक लगाना इसका मतलब राम भक्तों का अपमान करना है क्योंकि प्रधानमंत्री आदेश दे रहे हैं कि जनता को मंदिर में भगवान राम लला के दर्शन के लिए कब जाना चाहिए जबकि अभी तो मंदिर पूर्ण रुप से तैयार भी नहीं हुआ है। इसका स्पष्ट संदेश यह है कि भाजपा राम मंदिर का समय से पूर्ण उद्घाटन समारोह आगामी लोकसभा चुनावों में इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कर रही है।

कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई है कि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन करने से भाजपा को केवल मात्र नुकसान ही होगा, कारण कि राज्य सरकार ने इस महान अवसर पर आम जनता समारोह में सम्मिलित होने पर पाबंदी लगा दी है इस फैसले से वो लोग भड़क जाएंगे जो भक्त भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह का प्रत्यक्षदर्शी होना चाहते हैं।

बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए गठित "रेरा" का पूरा महकमा रिटायर्ड अफसरों के भरोसे

- **रजिस्ट्रार से लेकर असिस्टैंट रजिस्ट्रार के पदों पर सेवानिवृत अफसर तैनात हैं। ठेके पर नियुक्त कर्मचारी डिप्टी रजिस्ट्रार तथा असिस्टैंट रजिस्ट्रार का जिम्मा संभाल रहे हैं।**
- **मजेदार बात यह है कि, भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों राजस्थान के सरकारी विभागों से रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी हटाने के आदेश दिए थे, जिस पर स्वायत्त शासन विभाग ने 11 अफसरों को हटाया भी था।**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर 13 जनवरी। राजस्थान में बिल्डरों की मनमानी रोकने और आमजन को समय पर आवास मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में गठित, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का पूरा महकमा आज रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे पर चल रहा है।

सूत्रों के अनुसार, रेरा रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भी जो अधिकारी लगे हुए हैं, वे रिटायर्ड हैं। इसके साथ ही कई अधिकारी तो ऐसे हैं, जिनकी तनख्वाह हर माह दूसरे विभागों से उठ रही है, लेकिन वे पिछले करीब 5 सालों से रेरा में टिके हुए हैं। मजेदार बात यह है कि, ठेके पर नियुक्त पुनीत कपूर डिप्टी रजिस्ट्रार तथा ऋषभ शर्मा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जिम्मा संभाल रहे हैं। जबकि भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों राजस्थान के सरकारी विभागों से रिटायर्ड अधिकारी हटाने के आदेश दिए थे, जिस पर स्वायत्त शासन विभाग ने 11 अफसरों को हटाया भी था। सूत्रों के अनुसार, रेरा के न्याय निर्णायक अधिकारी रिछपाल सिंह कुलहरी भी जिला न्यायाधीश पद से रिटायर्ड हैं। रेरा रजिस्ट्रार रमेश चंद शर्मा भी सेवानिवृत हो चुके हैं, उनके बाद जॉइंट रजिस्ट्रार कुंती लाल जैन और गंगा विष्णु चौहान भी सेवानिवृत हो चुके हैं, जबकि प्रोजेक्ट सेल का जिम्मा संभाल रहे ज्वॉइंट रजिस्टार अर्पित संचेती भी पिछले करीब 5 वर्षों से रेरा में टिके हुए हैं, लेकिन ना तो उनकी नियुक्ति डेपुटेशन पर है और ना ही स्थायी। अर्पित संचेती की तनख्वाह हर माह नगर नियोजन विभाग से उठती है, लेकिन वे अपनी सेवाएं रेरा में दे रहे हैं। इसी तरह डिप्टी रजिस्ट्रार कैलाश चंद्र रघुवीर सिंह और अजीत कुमार तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुरारी लाल गुप्ता, मनोहर कुमार जैन और हरीश हर्ष भी रिटायर्ड हो चुके हैं, और इन सभी की आयु भी करीब 65 वर्ष है।

राजस्थान में निजी बिल्डरों की मनमानी रोकने और आम आदमी को इन बिल्डरों द्वारा बेचे गए आवास समय पर मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना हुई थी। इस विभाग का काम मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों तथा निजी बिल्डरों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें समय पर पूर्ण करवाना था। आज भी अधिकांश लोग बिल्डरों द्वारा समय पर फ्लैट और मकान मुहैया नहीं करवाने की शिकायत लेकर रेरा ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सूत्रों के अनुसार करीब 2000 से अधिक शिकायतें रेरा में अभी लंबित हैं। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले करीब 5 वर्षों में रेरा ने ऐसी कोई सूची भी जारी नहीं की है, जिसमें यह अंकित हो कि कितने लोग रेरा से लाभान्वित हुए हैं।

दिल्ली में तापमान 3.6 डिग्री

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। भारतीय मौसम विभाग की सूचना में कहा गया है कि दिल्ली में शनिवार को इस सर्दी के मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि इससे एक दिन पूर्व शुक्रवार 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा दिल्ली शहर के अनेक भागों में घना कोहरा छाया रहा। भा. मौ. वि. (आई.एम.डी.) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 जनवरी शनिवार का दिन इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा है तथा इस दिन का सबसे न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया और शहर के अनेक क्षेत्रों घना कोहरा छाया रहा।

- **शुक्रवार 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री था, पर शनिवार को तापमान उससे भी नीचे 3.6 डिग्री पर चला गया।**

मौसम विभाग ने दिल्ली में शीतलहर चलने को लेकर भी रैड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग कहा है कि पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के लिए कड़ाके की ठंड के चलते रैड अलर्ट जारी किया गया है तथा राजस्थान के लिए भी यलो अलर्ट जारी किया गया है यहां ठंड और कोहरे के हालात रहेंगे। आई.एम.डी. पहले भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली में 14 जनवरी तक भयंकर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी।

'चुनाव नतीजों के 40 दिन बाद भी नेता प्रतिपक्ष नियुक्त क्यों नहीं हो पाया?'

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कांग्रेस से सवाल किया

- **राठौड़ ने कहा कि, 19 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, पर दुर्भाग्य की बात है कि, कांग्रेस की गुटबाजी के कारण अभी तक भी नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं हो पाया है।**
- **राठौड़ ने कहा कि, मंत्रिमण्डल के गठन में विलम्ब पर बयानबाजी करने वाले कांग्रेसी नेताओं को अपने गिरेबां में झांक कर देखना चाहिए।**

जयपुर, 13 जनवरी (का.सं.)। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में विलंब को लेकर प्रतिदिन अनर्गल बयानबाजी करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिये कि कांग्रेस पार्टी चुनाव परिणामों के करीब 40 दिन बाद भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रही है। राठौड़ ने कहा कि 19 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू होने वाला है लेकिन दुर्भाग्य है कि आपसी अंतर्कलह के कारण कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला तक नहीं हो पाया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्तियां कर दी लेकिन राजस्थान में गुटबाजी का स्तर इस कदर चरम पर है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं किया जा सका है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के साथ न्याय नहीं होने की बात कहने वाले कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट अपनी पार्टी की चिंता करें तो बेहतर होगा।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के विगत पांच वर्ष के कार्यकाल गहलोत वर्सेज पायलट गुट की लड़ाई प्रदेश की जनता ने देखी है। 5 साल में राजस्थान का बंटाधार करने वाली कांग्रेस पार्टी को अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता करनी चाहिये। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष के पद जितने भी सदस्य नहीं थे। इस वर्ष 2024 में भी होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहले जितनी भी सीटें नहीं जीत पायेगी। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

अयोध्या में आज से नवदिवसीय अमृत महोत्सव शुरू

अयोध्या, 13 जनवरी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में चित्रकूट धाम के तुलसी पीठाधीश्वर पद्मविभूषण जगतगुरू रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के नवदिवसीय अमृत महोत्सव का रविवार को दिव्य शुभारंभ हो रहा है।

महोत्सव में देश के संत, राजनीतिक व फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। अमृत महोत्सव का यह नव दिवसीय आयोजन रामानंद मिशन के तत्वावधान में अयोध्याधाम पंचकोसी परिक्रमा स्थित बड़ा भक्तमाल की बगिया पर रविवार 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक हो रहा है। नवदिवसीय महोत्सव के क्रम में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ, श्रीरामकथा संवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हनुमान महायज्ञ में सवा करोड़ से अधिक आहुतियां डाली जायेंगी।

इस संबंध में तुलसीपीठाधीश्वर जगतगुरू रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने शनिवार को प्रेसवार्ता में कहा, "यह हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि, साढ़े पांच सौ वर्षों बाद श्रीरामलला सरकार अपने दिव्य-भव्य, नव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए न जानें हमारी कितनी पीढि य़ा चली गईं लेकिन वह रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को नही देख सकीं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जो हम सबके लिए हर्ष और गौरव का विषय है।"

बिहार में 6 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है।

माकपा ने भी तीन लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की मांग की है। इन सीटों पर दलों के बीच सहमति बनने के आसार नहीं दिख रहे हैं, इसलिये, कम से कम 6 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की आशा है।

नीतीश कुमार की जद (यू) के बाहर निकलने से, भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. गठबंधन पर स्पष्ट रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन भगवा पार्टी 22 जनवरी के बाद, दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुटों सहित, छोटे दलों के साथ, राम मंदिर की लहर का फायदा उठाते हुये, जीतने की आशा रखती है। चुनावी रणनीतिकार, प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि किशोर ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है लेकिन पिछले तीन दशकों से लालू और नीतीश के कुशासन के खिलाफ उनका अथक अभियान, भाजपा की मदद कर सकता है।

खड़गे होंगे इंडिया ब्लॉक के चीफ और ...

- **इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए पूर्व में ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने समर्थन दिया था। सभी ब्लॉक नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।**
- **इंडिया ब्लॉक की "फिज़िकल" बैठक आगामी अंतरिम बजट सत्र से पहले या सत्र के दौरान हो सकती है।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के रुप में प्रस्तावित किया गया, लेकिन खड़गे द्वारा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करने के बाद ही उनके नाम की घोषणा की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ही गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि दोनों ही आश्वस्त हैं कि भाजपा को हराने के लिए उन्हें किसी अन्य पार्टी की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 42 और 80 सांसद लोकसभा में भेजने वाले क्रमशः बंगाल और यूपी की जमीनी राजनीतिक वास्तविकर्ताओं से यह बात मेल नहीं खाती।

शिव सेना (यू.बी.टी.) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। इसमें भाग लेने के लिए उन्होंने संजय राउत को अधिकृत किया था, लेकिन राउत भी शामिल नहीं हो पाए।

खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया और इण्डिया गठबंधन के सभी नेताओं ने उसे स्वीकार किया। नेताओं ने सीट शेयरिंग वार्ताओं की प्रगति पर भी चर्चा की और संकल्प लिया कि इस काम को शीघ्राति शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

संयुक्त रणनीतियां बनाने और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव सम्बंधित मुद्दों को लेकर अन्तरिम बजट सत्र के दौरान या उससे पहले गठबंधन की एक नॉन वर्चुअल मीटिंग होने की उम्मीद है।

तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी मीटिंग में भाग लिया। उन्होंने बताया कि वह "पोंगल" के बाद सीट शेयरिंग वार्ताएं पूर्ण कर लेंगे।

गठबंधन की पार्टियां ऐसा महसूस करती हैं कि ऐसे वक्त में, जब भाजपा गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को लुभाने के लिए सक्रिय रुप से अभियान चला रही है, खड़गे का इण्डिया गठबंधन बनना वंचित वर्ग के एक बड़े तबके के वोटों को उनकी ओर लामबंद करेगा।

कांग्रेस के खिलाफ एक प्रयास के तहत तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) इण्डिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग से अनुपस्थित रही, हालांकि उसने कहा कि वह गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही उसने एक परन्तु यह भी लगा दिया कि कांग्रेस को बंगाल में अपनी हद जान लेनी चाहिए।

टी.एम.सी. ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण ममता वर्चुअल मीटिंग में भाग नहीं ले सकेंगी।

टी.एम.सी. ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की हैं, जिसे कांग्रेस अपर्याप्त मानती है।

लोकसभा में टी.एम.सी. के पार्टी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने के पिछले हफ्ते संकेत देते हुए कहा था कि उसके साथ यदि वार्ताएं विफल हो गईं तो पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं टी.एम.सी. के मुखर आलोचक माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही कहा था कि पार्टी टी.एम.सी. से सीटों की भीख नहीं मागेंगी।

स्थिति से सुपरिचित कई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से टी.एम.सी. तीन या चार सीटें कांग्रेस को देने का विचार कर सकती हैं, लेकिन वाम पार्टियों के लिए नहीं, क्योंकि ममता की नज़रों में भाजपा से बड़ी दुश्मन माकपा है।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां टी.एम.सी. 22, कांग्रेस 2 और भाजपा 18 सीटों पर विजयी रही थी। चौधरी बहरामपुर सीट से चुनाव जीते थे, जबकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री रहे अबू हासम खान मालदा दक्षिण से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते।

टी.एम.सी. और कांग्रेस पहले तीन बार आपस में गठबंधन कर चुके है। एक बार तो वर्ष 2001 के विधानसभा चुनाव में, वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में और वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में। गत 34 वर्षों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में रहे सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा का सरकार को उस गठबंधन के कारण ही सत्ता से बाहर किया जा सका था।

भाजपा का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करेगी जिन पर उसने पराजय का स्वाद चखा है। प्रदेश इकाइयों से कहा गया है कि वे ऐसी तैयारी करें ताकि पार्टी के पास उम्मीदवारों के अच्छे विकल्प हों। इसमें वह ऐसे नेताओं को भी सम्मिलित करेगी, जो अन्य पार्टियों को छोड़कर आए हैं और भाजपा में शामिल हुई हैं। भाजपा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के बाद अपनी चुनावी गतिविधियों को द्रुतगति प्रदान करेगी। पार्टी वर्तमान सांसदों की उम्मीदवारी पर 9 फरवरी को संसद का बजट समाप्त होने पर विचार करेगी। भाजपा ने 2 से 5 सीटों के लिए लगभग 130 क्लस्टर्स गठित किए हैं जिन पर पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सोमवार के बाद रैलियां एवं जन सभाएं करेंगे। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908